Faridabad Plot Built Properties in all Sectors

SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11,
Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288

Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES

(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa

24, Hours Service

Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 23 अंक 11 शनिवार, फरीदाबाद, 1-15 मई, 2010 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

पुलिस की नीयत साफ़ हो तो हो ही नहीं सकते अपराध

जनसाधारण की जान-माल की सुरक्षा के लिए बनाये गये पुलिस विभाग को इतनी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि इनके सही व नेकनीयती से इस्तेमाल करने पर अपराधी तत्वों की नकेल पूरी तरह से कसी जा सकती है। लेकिन इसके विपरीत, इन शक्तियों का इस्तेमाल अपराधों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है जिससे पुलिस को अच्छी-खासी लूट प्राप्त होती है। रही बात सुरक्षा की तो यह तो केवल अति विशिष्ट लोगों के लिए ही रह गई है।

पुलिस की बदनीयती एवं इसमें फ़ैले भ्रष्टाचार का कारण मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें पुलिसकर्मियों की भर्ती से लेकर नियुक्ति तक सब कुछ लेन-देन के आधार पर आधारित है। योग्यता एवं पात्रता का स्थान पूरी तरह से भाई-भतीजावाद ने ले लिया है। महकमें में सिपाही से लेकर डीएसपी तक भर्ती होने के लिए अब उम्मीदवार की योग्यता कोई पैमाना नहीं रह गई है। इसी के चलते ही अशोक श्योराण जैसे डीएसपी और डॉ.सुनील जैसे एस.आई.भर्ती होकर आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भ्रष्ट एवं निकम्मे केवल डीएसपी रैंक तक के ही होते हैं। सीधे आईपीएस भर्ती होकर आने वाले कई लोगों ने भ्रष्टाचार के रिकार्ड ही तोड़ रखे हैं। लेकिन इन सब के पीछे राजनीतिक प्रश्रय एक अनिवार्य कारक है। यदि राजनेता भ्रष्ट एवं निकम्मे अफ़सरों को प्राथमिकता देने के बजाये उनकी नकेल कस कर रखें तो किसी अफ़सर की क्या मजाल जो जरा भी गड़बड़झाला कर पाये। लेकिन राजनेताओं की चापलूसी एवं उनके उलटे-पुलटे काम केवल भ्रष्ट अफ़सर ही कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें प्राथमिकता प्राप्त होती ही है।

जनता की सुरक्षा पुलिस एजेंडे में ही नहीं!

पुलिस की कार्यशैली को देखते हुए यह कहने में ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं कि जनता की सुरक्षा के लिए बनी पुलिस के एजेंडे में जनता की सुरक्षा दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आती। आये दिन चेन झपटमारी, सरे राह चलते-चलते दिन दहाड़े लूट की वारदातें होना, कानून एवं व्यवस्था किस चिड़िया का नाम है, शायद ही कोई जानता हो। 26 अप्रैल को दिन के साढ़े दस बजे सेक्टर-9 जैसे आबाद क्षेत्र से 19 लाख रुपये लूट ले जाना सबसे ताज़ी मिसाल है। इस लूट के लिए पुलिस उल्टे पीड़ित एवं लुटे हुए लोग़ों को ही दोषी बता रही है। पुलिस का कहना है कि वे अकेले इतनी बड़ी रकम लेकर निकले ही क्यों थे? उन्होंने निकलने से पहले पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? सर्वविदित है कि पुलिस सुरक्षा मांगने पर कैसी सुरक्षा और कैसे-कैसे जवाब सुनने को मिलते हैं। पुलिस की छवि इस कदर खराब कर दी गई है कि आम आदमी की कोशिश होती है कि उसे पुलिस से संपर्क ना ही करना पड़े। इसके अलावा कड़वी सच्चाई है यह भी है कि पुलिस है कहां? थानों में संतरी खड़ा करने के लिए सिपाही तक तो हैं नहीं, बात करते हैं प्रत्येक रकम को ले जाने वाले को सुरक्षा देने की। इतने बड़े शहर में रोज़ाना हज़ारों व्यक्ति लाखों रुपये इधर से उधर ले कर चलते हैं, इन सबसे व्यक्तिगत सुरक्षा देना संभव भी कैसे हो सकता है? उक्त वारदात होने के तुरंत बाद पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, लेकिन जब कोई संपर्क न हो सका तो आसपास खड़ी पीसीआर जिप्सी तक पहुंचे। 15 मिनट तक जब उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्हें खुद चल कर थाना सेक्टर-8 में जाना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद भी पुलिस का रवैया कोई त्वरित नहीं, बल्कि उदासीन था। इसके चलते वीटी करने व नाकेबंदी करने में अत्यधिक विलंब हुआ।

हाउस टैक्स दुबारा लगाने पर सरकार की किरकिरी

29 नवंबर, 2007 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हाऊस टैक्स समाप्त कर दिया। ऐसा करके मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपना चुनावी 'वादा' पूरा कर जनता को राहत दी। पर अब सरकार ने यह फैसला किया है कि हाऊस टैक्स फिर से लगाया जायेगा। इससे राज्य के लोग़ अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग़ यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है? अगर हाऊस टैक्स लिये बिना काम नहीं चलने वाला था तो फिर इसे हटाया ही क्यों? दरअसल, हाऊस टैक्स के मामले में अपने फैसले से पलट जाने के कारण सरकार की भारी किरकिरी हो रही है। जनता ऐसे ही टैक्सों के बोझ तले दबी हुई है। हाऊस टैक्स खत्म किये जाने से उसे थोड़ी राहत मिली थी, पर अब उसे फिर से यह टैक्स देना पड़ेगा। सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करने जा रही है।

अब जब हाऊस टैक्स दुबारा शुरू किया जायेगा तो जनता में रोष होना स्वाभाविक है, पर इससे निगम को क्या मतलब है? वह तो अधिसूचना जारी होते ही हाऊस टैक्स वसूलने में लग जायेगी। हां, इसका खामियाजा हुड्डा एवं उनकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। भूलना नहीं होगा कि हुड्डा ने चुनावी वादे के तहत हाऊस टैक्स को समाप्त करवाया था।

सवाल है, सरकार ऐसा करके अपनी किरकिरी क्यों करवा रही है?

सरकार का कहना है कि ऐसा वह मजबूरी में कर रही है। बिना हाऊस टैक्स वसूले वह केंद्र सरकार को अपनी हिस्सेदारी नहीं दे सकती और ऐसा नहीं करने पर शहरी विकास के लिए मिलने वाला केंद्र सरकार का ग्रांट उसे नहीं मिल सकता। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल स्कीम के तहत राज्य सरकारों को अच्छा-खासा ग्रांट देती है, पर इसके लिए राज्य सरकार एवं नगर निकाय संस्थाओं को अपना-अपना हिस्सा देना पड़ता है। इस मामले में ग्रांट पाने के लिए फरीदाबाद नगर निगम अपना हिस्सा दे पाने में अपने आप को अक्षम पा रहा है। 'कर्ज लेकर घी पीने' की उक्ति को चरितार्थ करने वाले नगर निगम ने अपनी हिस्सेदारी देने के लिए पहले कर्ज लेने की पूरी कोशिश की, पर इसमें उसे सफलता नहीं मिली।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का तमाशा

■ **मनोज कुमार झा**

जब से आईपीएल का तमाशा शुरू हुआ है, क्रिकेट प्रेमियों में नशा-सा छा गया है। ऐसे भी यह खेल निठल्लों का है। कामकाजी आदमी इस लंबे चलने वाले खेल को देख कर अपना समय नहीं गंवा सकता। इस बात को क्रिकेट के संचालकों ने समझ लिया और बड़ी चालाकी के साथ टेस्ट मैच जो तीन-चार दिन चलता था और तब जा कर हार-जीत का फ़ैसला होता था, की जगह एक दिनी मैच ट्वेंटी-ट्वेंटी शुरू किया। यह छोटा मैच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यद्यपि लोकप्रिय तो टेस्ट मैच भी होते थे और जब टीवी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तब लोग़ ट्रांजिस्टर कानों में लगाये क्रिकेट की कमेन्टरी सुनते थे।

दफ़तरों तक में काम बंद हो जाता था। न छात्र पढ़ते थे, न शिक्षक पढ़ाते थे। जिनके पास ट्रांजिस्टर न होते, वे आते-जाते लोग़ों से स्कोर पूछा करते थे। उस ज़माने में क्रिकेट के नायक सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, बिशन सिंह बेदी, किरमानी, प्रसन्ना, करसन घावरी जैसे खिलाड़ी थे। बाद में जीते जी लीजेंड बन जाने वाले कपिलदेव जैसे खिलाड़ी सामने आये जिन्होंने भारतीय टीम को विश्व विजेता टीम बना दिया।

उन्हीं दिनों गैरी पार्कर नाम के आस्ट्रेलियायी अरबपति ने क्रिकेट के खेल को एक नया स्वरूप देना चाहा। उसने दुनिया भर की टीमों को अपने यहां बुला कर रात में बिजली की रोशनी में क्रिकेट का सर्कस शुरू किया। खिलाड़ी जहां पहले सफ़ेद कपड़े पहना करते थे, उसने उनके कपड़े रंगीन कर दिये। मैच दिन के बजाय रात में हुआ करते थे। उसने भी पूरी दुनिया से चुन-चुन कर किक्रेट खिलाड़ियों को इस सर्कस में भर्ती किया था। उसका यह तमाशा उन दिनों काफ़ी सफ़ल हुआ।

अब उपरोक्त तमाशे के तर्ज पर आईपीएल का तमाशा शुरू किया गया है। आईपीएल के मैचों में भाग लेने वाली टीमों को इस देश के धनपतियों ने बोली लगा कर खरीद लिया है। इसके अलावा एक-एक खिलाड़ियों को भी करोड़ों-करोड़ में खरीदा गया है। मुंबई की टीम अंबानी ने खरीदी है तो कोलकाता की टीम शाहरुख खान ने। बंगलौर की टीम प्रसिद्ध शराब निर्माता विजय माल्या ने खरीद रखी है तो मोहाली की टीम फिल्मी नायिका प्रीती जिंटा ने खरीदी है।

डीएलएफ ने भी कोई टीम खरीद ली है। इन आईपीएल मैचों को फटाफट क्रिकेट कहा जाता है, क्योंकि सारा खेल बस बीस ओवरों का ही होता है। इन खेलों में राष्ट्रीयता जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। प्रत्यके टीम में थोक के भाव से विदेशी खिलाड़ी खरीद कर भर्ती किये गये हैं। कई टीमों में ये कप्तान की भूमिका में हैं, जैसे राजस्थान रोयाल्स टीम में। इस तरह यहां पूरा अंतरराष्ट्रीयवाद है। सचमुच ग्लोबलिज़्म के प्रत्यक्ष दर्शन यहीं होते हैं। इन खेलों में खिलाड़ी तो पैसे में डूब-उतरा ही रहे हैं, टीमों के मालिक भी अरबों में खेल रहे हैं। कुल मिला कर इन खेलों में खेल की सारी मर्यादायें ताक पर रख दी गई हैं। पैसा नंगा होकर नाच रहा है।

क्रिकेट के नाम पर खुली लूट

इस खेल में जो करोड़ों-अरबों रुपये लगाये जा रहे हैं, वे किनके पैसे हैं? वे पैसे जनता की लूट के पैसे हैं। काला धन तिजोरियों से बह निकला है। स्याह को सफ़ेद बनाने का यह निराला मौका है। तभी तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों से लेकर मंत्रियों और नौकरशाहों के पैसे नाम से अथवा बेनामी इस खेल में लगाये जा रहे हैं। सट्टेबाजों की बन आई है। अभी एक मंत्री की कुर्सी इस खेल ने छीनी है और वह भी नहीं छिनती अगर लूट के हिस्से पर कहा-सुनी न होती। अब जा कर जब सारा भांडा फूटा तो इस खेल के प्रमुख संचालक पर शिकंजा कसा जा रहा है और उनकी भी छुट्टी कर दी गई, लेकिन उनका कहना है कि वे अभी भी अपने पद पर हैं। इन हालात में अभी से ही राजनेताओं के राजनेता पुत्र अथवा राजनेत्री पुत्री अखबारों में बयान दिये जा रहे हैं कि उन्होंने इस खेल में पैसा नहीं लगाया है।

यानी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। कया विडंबना है कि संसद में चर्चा का प्रमुख विषय ही आईपीएल और क्रिकेट हो गया है। जनता की समस्याओं पर बातचीत करने के लिए समय नहीं है। अगर कोई मुद्दा उठता भी है तो शोर-शराबे के अंधड़ में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। पर क्रिकेट को देखने और सुनने की पूरी व्यवस्था कर ली जाती है। इस खेल से मीडिया का पेट भी भरा जा रहा है। आईपीएल के (पूर्व) कमिश्नर ललित मोदी कहते हैं कि इस तमाशे को विदेशों में भी ले जाया जायेगा। क्यों नहीं? जब विदेशी खिलाड़ी इन टीमों में थोक के भाव खेल रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए विदेशों के लोग़ आखिर क्यों नहीं तैयार होंगे? वैसे ललित मोदी के हटाये जाने पर इस खेल के पीछे का सारा खेल सामने आ रहा है और गंदगी बह निकली है। दरअसल, यह सब इसलिए हुआ कि इस खेल के नाम पर लूट के धन के बंटवारे का सवाल अब चरम पर पहुंच गया।